



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

HC/S
E/S/98

सं० 65]
No. 65]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 1998/चैत्र 4, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 1998/CHAITRA 4, 1920

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट अनुभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1998

फा. सं 15 (10)-बी (डी)/98—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

अन्तरिम बजट 1998-99

वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा का भाषण
25 मार्च, 1998

महोदय,

मैं वर्ष 1998-99 का अन्तरिम बजट प्रस्तुत करने आ रहा हूँ।

2. यह अन्तरिम बजट लेखानुदान के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान अपना कार्य कर सके और अनिवार्य व्यय को पूरा कर सके। अनुदान मांगों और वार्षिक वित्तीय विवरण को जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए हैं, कुछ सप्ताह के समय में नियमित बजट प्रस्तुत करते समय संशोधित किया जाएगा और उन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा। मैं आज ही वित्त विधेयक भी प्रस्तुत करूँगा जिसमें पूरे वर्ष के लिए वर्तमान कर संरचना को ही जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

3. जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है हम इस बात को देखकर चिन्तित हैं कि वर्ष 1997-98 में सम्पूर्ण आर्थिक विकास की गति धीमी होकर केवल 5 प्रतिशत रह गई है, कृषि क्षेत्र ने 2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दिखाई है, उद्योग की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है और जनवरी, 1998 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान इसकी वृद्धि दर औसतन केवल 4.6 प्रतिशत रही है और जनवरी, 1998 तक हाल के प्रत्येक तीन महीनों में जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, निर्यातों ने डालर मूल्य में नकारात्मक वृद्धि दिखाई है, महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा क्षेत्रों की अड़चनें सर्वविधित हैं, पूंजी बाजार में मंदी और निराशा की स्थिति बनी हुई है और राजकोषीय हालात अनुमान से कहीं अधिक खराब हैं।

4. मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इन प्रवृत्तियों और कठिनाईयों को 1998-99 का नियमित बजट बनाते समय पूर्ण रूप से दृष्टिगत रखा जाएगा जिसे मैं भवनीय सदस्यों के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत करूँगा। सामान्य आर्थिक समीक्षा को भी इसी के साथ सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नियमित बजट में कृषि एवं उद्योग को स्फुरित करने, निर्यातों को पुनः गतिशील बनाने, सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डा के अनुरूप विदेशी निवेश के

अधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करने, बुनियादी सुविधाओं की दशा सुधारने के लिए निर्णायक कदम उठाने, वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशों के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रणाली तैयार करते हुए सरकारी क्षेत्र के सुधार में तेजी लाने और कठोर राजकोषीय अनुशासन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। हमारी सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डा में शामिल दूसरी नई दिशाओं को भी यह प्रतिबिम्बित करेगा।

5. विदेशी आर्थिक परिवेश असामान्य अनिश्चितता से परिपूर्ण है। पिछले नौ महीनों में अधिकांश पूर्वी एशियाई देश आर्थिक संकट की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसके कारण अब तक तेजी से बढ़ रही अनेक अर्थ व्यवस्थाओं के लिए भारी आर्थिक और वित्तीय विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई दशकों से बनी हुई हमारी अर्थव्यवस्था की यह अन्तर्निहित शक्ति एवं सामर्थ्य है कि हम अपना सिर ऊँचा उठाए रखने में समर्थ बने हुए हैं और एशियाई क्षेत्र में फैले इस आर्थिक झंझावात के सामने हमने घुटने नहीं टेके हैं। परन्तु हमें सतत रूप से सतर्क एवं चौकस रहना चाहिए और अपनी आर्थिक नीतियों को दूरदृष्टि एवं लचीलेपन के साथ चलाना चाहिए। कठिन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद कम मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा संतुलन के साथ तभी हम आर्थिक वृद्धि को पाना सुनिश्चित कर सकते हैं।

वर्ष 1997-98 के लिए संशोधित अनुमान

6. वर्ष 1997-98 के लिए संशोधित अनुमानों का सारांश देते हुए सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू कर वसूलियों और विनिवेश प्राप्तियों में भारी गिरावट है। यह अनुमान किया गया है कि केन्द्र के लिए निवल कर राजस्व केवल 99,158 करोड़ रुपए है जो बजट अनुमानों की तुलना में 14,236 करोड़ रुपए की कमी या 12.5 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित करता है। यह कमी मुख्यतः आयतों की कम मात्रा और कम यूनिट मूल्य दोनों के कारण काफी कम सीमा शुल्क राजस्व के कारण है। उत्पाद शुल्क में गिरावट असामान्य रूप से निम्न औद्योगिक वृद्धि का परिणाम है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशों से प्राप्तियों का प्रश्न है, वह 4800 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 3,894 करोड़ रुपए कम होंगी। कुल व्यय के संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों की तुलना में 3069 करोड़ रुपए अधिक हैं। यह वृद्धि लघु बचत संग्रहणों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों, की अकेली मद पर हुए 4432 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय से कम है। इन संग्रहणों में वर्ष के दौरान आशातीत वृद्धि हुई है। इसका निवल परिणाम यह है कि सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के बजट लक्ष्य से बढ़कर राजकोषीय घाटा 6.1 प्रतिशत हो गया है।

परन्तु यदि लघु बचत ऋणों के कारण व्यय में वृद्धि को इसमें शामिल न किया जाए तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लघु बचत ऋणों के लिए बजट से वृद्धि हेतु समायोजित राजकोषीय घाटा 1997-98 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5.8 प्रतिशत होगा।

7. जहां तक स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना (वी.डी.आई.एस.) के अंतर्गत अनुमानित 10,050 करोड़ रुपये की प्राप्ति का प्रश्न है, मेरे पूर्ववर्ती मंत्री जी ने दिसम्बर, 1997 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों का 77.5 प्रतिशत अर्थात् 4379 करोड़ रुपए राज्यों को देने के निर्णय की घोषणा की थी। प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं एक कदम और आगे बढ़ा हूँ और 1997-98 के पूरे वर्ष के लिए वी.डी.आई.एस. की प्राप्तियों के संशोधित अनुमानों का 77.5 प्रतिशत राज्यों को देने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य अतिरिक्त रूप से 3215 करोड़ रुपए प्राप्त करेंगे और इस प्रकार यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में कुल 7594 करोड़ रुपए दी जाएगी।

8. इसके अलावा, मैं विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ ताकि चालू वित्तीय वर्ष में सभी लम्बित दावों का निपटारा हो सके।

9. इस प्रकार इन दो निर्णयों के सम्मिलित रूप से राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में 8594 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। यह राज्यों को अधिक सहायता देने की हमारे राष्ट्रीय एजेन्डा की वचनबद्धता के पूर्णतः अनुरूप है।

1998-99 के लिए बजट अनुमान

10. तैयार किए गए बजट के अनुसार, चालू वर्ष में 235245 करोड़ रुपए की तुलना में 1998-99 का कुल व्यय 264988 करोड़ रुपए होने का अनुमान किया गया है। इसमें से केन्द्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए सकल बजटीय सहायता 64461 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि चालू वर्ष में यह धनराशि 60630 करोड़ रुपए थी। नियमित बजट में, वार्षिक आयोजना 1998-99 के लिए बजटीय सहायता के स्तर और मर्दों की पुनरीक्षा करने का हमारा प्रस्ताव है। नवीं योजना की पुनरीक्षा और बजट अनुमानों को संशोधित करने का हमारा दृढ़ संकल्प है ताकि वह हमारी विचारधारा और प्राथमिकताओं को प्रदर्शित कर सके। नियमित बजट के लिए इस कार्य को यथासमय पूरा करने का हमारा प्रस्ताव है जिसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

11. चालू वर्ष में 174,615 करोड़ रुपए की तुलना में 1998-99 के आयोजना भिन्न व्यय का अनुमान 200,527 करोड़ रुपए लगाया गया है जो 25912 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। संशोधित अनुमान 97-98 से वृद्धि के मुख्य कारण व्याज अदायगियों में 10,300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, पेंशन में 4,747 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, रक्षा व्यय में लगभग 3,900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी और बड़ी आर्थिक सहायताओं में लगभग 1500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है।

12. कराधान की वर्तमान दरों पर कर राजस्वों सहित कुल गैर ऋण प्राप्तियां 168,173 करोड़ रुपए होने का अनुमान किया गया है जबकि कुल व्यय 264,988 करोड़ रुपए अनुमानित है। 1998-99 के इन अनुमानों से होने वाला राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6 प्रतिशत होगा। यह स्पष्टतः स्वीकार्य नहीं है और नियमित बजट में समुचित उपायों से इसे उचित सीमा तक कम करने का हमारा प्रयास होगा।

13. यद्यपि इस संबंध में हमारी विशिष्ट कार्यनीतियों को तैयार करने में हमें कुछ समय लगेगा, फिर भी स्थापना से संबंधित व्यय की वृद्धि को रोकने, और गत वर्षों में हुई प्राप्तियों में कमी से बचने के लिए यथाशीघ्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक होगा।

14. माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों की साझेदारी के लिए दसवें वित्त आयोग ने एक वैकल्पिक योजना की सिफारिश की थी जिसके अन्तर्गत लगभग सभी केन्द्रीय करों की सकल प्राप्तियों का 29 प्रतिशत राज्यों को दिया जाना है। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन रही है। 17 जुलाई, 1997 को आयोजित अन्तराज्यीय परिषद की तीसरी बैठक में हुई सहमति के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को लागू करने के लिए, जिसका सभी राज्यों ने समर्थन किया है, हमारा इरादा समर्थकारी संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का है।

15. अन्त में, इस सम्माननीय सदन के आदरणीय सदस्यों को मैं आश्चस्त करना चाहता हूँ कि सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डा में निहित आर्थिक लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिये मैं हर संभव प्रयत्न करूँगा। आर्थिक सुधारों को सुदृढ़, व्यापक और तेज किया जाएगा। हमारा उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से एक मजबूत और गतिशील राष्ट्र बनाना है जो विश्व की अर्थ व्यवस्था में विश्वास और शक्ति के साथ भागीदारी करेगा। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए दृढ़-संकल्प हैं जिसमें भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और अभावग्रस्तता के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

16. इन शब्दों के साथ, मैं इस सम्माननीय सदन में बजट पेश करता हूँ।

जे. एस. माथुर, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Budget Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1998

No. F. 15(10)-B(D)/98.— The following is issued for general information:—

Interim Budget 1998-99

Speech of Shri Yashwant Sinha,

Minister of Finance

25th March, 1998

Sir,

I rise to present the Interim Budget for 1998-99.

2. This Interim Budget is being presented for the purpose of a Vote-on-Account to enable the Government to carry on its business and meet essential expenditure during the first four months of the next financial year. The Demands for Grants and the Annual Financial Statement, which are for the full financial year, will be revised and finalised at the time of presentation of the Regular Budget in a few weeks time. I shall also introduce a Finance Bill today, which merely seeks to continue the existing tax structure for a full year.

3. As regards the economic situation, we are concerned to note that overall economic growth has slowed to 5% in 1997-98, agriculture has registered negative growth of 2%, industry continues to be in the doldrums averaging only 4.6% growth over the 12 months up to January, 1998, and exports have recorded negative growth in dollar terms in each of the three most recent months up to January, 1998, for which data are available. The bottlenecks in key infrastructure sectors are well known, the capital market has been lacklustre and the fiscal situation is significantly worse than expected.

4. I would like to assure the House that these trends and difficulties will be fully addressed in the Regular Budget for 1998-99 that I shall bring before the Hon'ble Members shortly. The usual Economic Survey will also be presented to the House at that time. The Regular Budget will seek to impart the necessary stimulus to agriculture and industry, restore dynamism to exports, encourage larger flows of foreign investment in line with the National Agenda for Governance, take decisive initiatives to improve the state of infrastructure, strengthen the financial system, accelerate the reform of the public sector while building a strong and transparent system for PSU disinvestments, and bring about strict fiscal discipline. It will also embody other new directions included in our National Agenda for Governance.

5. The external economic environment is fraught with unusual uncertainty. The East Asian crisis has swept across much of Asia in the last nine months, bringing massive economic and financial disruption to several hitherto fast growing economies. It is the inherent strength of our economy, built over decades, which has enabled us to hold our heads high and not succumb to the economic gales that have been sweeping through the Asian region. But we must remain ever watchful and vigilant and conduct our economic policies with foresight and flexibility. Only then can we be sure of achieving rapid economic growth with low inflation and external stability despite the difficult international economic scenario.

Revised Estimates for 1997-98

6. Turning briefly to the Revised Estimates for 1997-98, the most noteworthy point is major shortfalls in tax collec-

tions and disinvestment receipts. Net tax revenues for the Centre are estimated at only Rs. 99,158 crore, reflecting a drop of Rs. 14,236 crore, or a 12.6% decline over Budget Estimates. The shortfall is primarily due to much lower customs revenue on account of both lower volume and unit price of imports. The decline in excise resulted from unusually low industrial growth. Receipts from PSU disinvestments are estimated to fall short of the Budget Estimates of Rs. 4,800 crore by Rs. 3,894 crore. The Revised Estimates for total expenditure are expected to exceed the Budget Estimates by only Rs. 3,069 crore. This is less than the additional expenditure of Rs. 4,432 crore incurred on account of the single item of loans to States and Union Territories against small savings collections, which have been exceptionally buoyant during the year. The net result is a deterioration of the fiscal deficit from the budget target of 4.5% of GDP to 6.1%. However, if the increase in expenditure attributable to small savings loans is excluded, the fiscal deficit, adjusted for the increase over budget in small saving loans to States and Union Territories, would be 5.8% of GDP in 1997-98.

7. In regard to collections under the Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS), estimated at Rs. 10,050 crore, my predecessor had announced a decision to devolve to the States 77.5% of the collections under the scheme up to the end of December, 1997, amounting to a sum of Rs. 4,379 crore. With the blessings of the Prime Minister, I propose to go a step further and to devolve to the States 77.5% of the Revised Estimates of VDIS collections for the full year 1997-98. As a consequence, the States will now receive an additional Rs. 3,215 crore, thus taking the total devolution on this account to Rs. 7,594 crore in the current financial year.

8. Furthermore, I propose to provide an additional sum of Rs. 1000 crore by way of Additional Central Assistance to States on account of externally aided projects in order to settle all pending claims in the current financial year.

9. Taken together, these two decisions will give to the States an additional sum of Rs. 8,594 crore in the current financial year 1997-98. This is fully in accord with the commitment in our National Agenda to extend greater assistance to States.

Budget Estimates for 1998-99

10. According to the Budget as prepared, total expenditure in 1998-99 is estimated at Rs. 2,64,988 crore against Rs. 2,35,245 crore in the current year. Of this, the gross budgetary support to the Central, State and the Union Territory Plans is placed at Rs. 64,461 crore against Rs. 60,630 crore in the current year. We propose to review the level and content of the budgetary support for Annual Plan 1998-99 in the Regular Budget. It is our firm resolve to review the Ninth Plan and to revise the Budget Estimates so that they reflect our thinking and priorities. We propose to complete this exercise in time for the Regular Budget which will be presented shortly.

11. Non-Plan expenditure in 1998-99 is estimated to be Rs. 2,00,527 crore against Rs. 1,74,615 crore in the current year, an increase of Rs. 25,912 crore. The main reasons for increase over RE 97-98 are on account of an increase of Rs. 10,300 crore in Interest Payments, an increase of Rs. 4,747 crore in Pensions, an increase of about Rs. 3,900 crore in Defence expenditure and an increase of about Rs. 1,500 crore in major subsidies.

12. Total non-debt receipts, including tax revenues at existing rates of taxation, are estimated at Rs. 1,68,173 crore, while total expenditure is estimated at Rs. 2,64,988 crore. The fiscal deficit emerging from these estimates for 1998-99 will be about 6% of GDP. This is clearly not acceptable and it will be our endeavour to bring it down to a reasonable limit in the Regular Budget through appropriate measures.

13. While it would take some time for us to formulate our specific strategies in this regard, immediate action is called for to contain the growth in establishment expenditure and initiate the process of PSU disinvestment at an early date to avoid shortfalls in receipts experienced in previous years.

14. Hon'ble Members are aware that the Tenth Finance Commission had recommended an alternative scheme for sharing of resources between the Centre and the States under which 29% of the gross proceeds of almost all Central taxes is to be assigned to the States. This recommendation has been under consideration of Government. On the basis of a consensus arrived at in the Third Meeting of the Inter-State Council held on July 17, 1997 the previous Government had decided to accept this scheme in principle. We intend to bring forward the enabling Constitution Amendment Bill to give effect to this decision which has been endorsed by all the States.

15. I would like to assure the Hon'ble Members of this august House that I shall make every effort in my Regular Budget to implement the economic goals enunciated in our National Agenda for Governance. Economic reforms will be deepened, broadened and accelerated. Our goal is to make India an economically strong and vibrant nation which will participate in the world economy with confidence and from a position of strength. We are determined to build an India in which there is no place for hunger, poverty, unemployment and deprivation.

16. With these words, I commend the Budget to this august House.

J.S. MATHUR, Addl. Secy. (Budget)